हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है। क्योंकि इनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है।–अज्ञात।

विचार-प्रवाह

देहरादून, शनिवार, 21 मई 2022

पेज थ्री

www.page3news.in

नियम–कानूनों की अनावश्यक जकड़न

यह बात पहले से कही जाती रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसे अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा शिद्दत से महसूस करते और व्यक्त करते रहे हैं कि सरकारी तंत्र का बेजा दखल देश में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने में बाधा बन रहा है।

अमन सिंह।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने एक बार फिर आम नागरिकों और खासकर उद्यमियों पर नियम–कानूनों की अनावश्यक जकड़न को कम करने की प्रक्रिया शुरू की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने विभिन्न विभागों के सचिवों को एक पत्र भेजकर उन्हें अपने दायरे में आने वाले उन कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने को कहा है, जो छोटे–मोटी चूकों या गलतियों को भी अपराध की श्रेणी में डाल देते हैं। ध्यान रहे, कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री की अपने आवास पर सीनियर आईएएस ऑफिसरों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा इस मसले पर भी चर्चा हुई थी। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री की इस पहल का मकसद न केवल विभिन्न एजेंसियों और न्याय प्रक्रिया पर पड़ रहे बोझ को कम करना है बल्कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना भी है। वैसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई नया अजेंडा नहीं है। काफी पहले से वह कहते रहे हैं कि सरकारों और सरकारी तंत्र के दायरे को कम करने की जरूरत है। यह बात पहले से कही जाती रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसे अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा शिद्दत से महसूस करते और व्यक्त करते रहे हैं कि सरकारी तंत्र का बेजा दखल देश में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने में बाधा बन रहा है।

इसी क्रम में याद किया जा सकता है कि दो साल पहले भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसी आशय का पत्र भेज कर उनसे यही गुजारिश की थी। अगर उस दिशा में कोई खास प्रगति इस बीच नहीं हो सकी तो उसके पीछे संभवतरू उतार–चढ़ाव वाला वह असाधारण दौर रहा, जिससे कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया को गुजरना पड़ा। इस पूरी अवधि में स्वाभाविक ही सरकार और टॉप ब्यूरोक्रेसी की प्राथमिकता बदली रही। अच्छी बात यह है कि अब जब सामान्य स्थिति बहाल होती दिख रही है, सरकार ने अपने उस अजेंडे पर अमल की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। वैसे इसमें दो राय नहीं कि यह जरूरी और उपयोगी पहल है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह बड़ी फिसलन भरी राह है।

नियम–कानूनों में ढील देने या इसकी जकड़न को कम करने के साथ यह खतरा भी जुड़ा हुआ है कि कहीं इस क्रम में कानून में ऐसे छिद्र न बन जाएं जो अपराधी तत्वों के लिए वरदान साबित हों। इसलिए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करते हुए आवश्यक और अनावश्यक के सवाल पर अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन फिर रेखांकित कर दिया जाए कि आगे बढ़ने की जरूरत अवश्य है। इससे न केवल उद्यमियों की राह आसान होगी और बिजनेस में इनोवेशन की गुंजाइश बढ़ेगी बल्कि सरकारी तंत्र के लिए भी बड़े और गंभीर अपराधों के उन्मूलन की कोशिशों पर ध्यान देना आसान होगा। साथ ही, अदालतों पर मुकदमेबाजी का बोझ भी इससे घटेगा।

हिंदू धर्म

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। योगी अश्विनी का मत यह है कि वेदों में कर्म को प्रधानता दी गई है। गीता भी कर्म को प्रधानता देता है इसलिए जो जिस कर्म को करेगा उस कर्म के अनुसार ही उसकी जाति होगी। हिंदू धर्म के जानकार पंडित जय गोविंद शास्त्री का मत भी योगी अश्विनी से मिलता जुलता है। इनका भी यही मत है कि शास्त्रों अन्य धर्म में जाने और अन्य धर्म से हिन्दू धर्म में आने की बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। पुराणों में कहीं भी धर्म को लेकर विभेद का जिक्र नहीं किया है। उन दिनों विभेद वंश को लेकर था क्योंकि उस समय वंशवाद का अस्तित्व था धर्म और जातिवाद का नहीं। कर्म के अनुसार व्यक्ति की जाति निर्धारित हो जाती थी। हालांकि अभी यह सवाल अनुत्तरित है कि जब हिंदू धर्मावलंबी कर्म के अनुसार अपनी जाति नहीं चुन सकते तो बाहर से इस धर्म में आए किसी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है।

संपादकीय

दोनों के बीच क्या फर्क

अखिलेश के मुकाबले तेजस्वी के बीस साबित होने की कई बुनियादी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यधारा की राजनीति से बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं। अब सारे फैसले अखिलेश अपनी समझ से ले रहे हैं लेकिन तेजस्वी को अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अनुभव का लगातार लाभ मिल रहा है। कब, कहां, कौन सा दांव आजमाना चाहिए, यह सलाह तेजस्वी अपने पिता से लेना नहीं भूलते, भले ही अंतिम फैसला खुद उनका हो। दूसरी वजह यह है कि तेजस्वी का जो इनर सर्किल है, उसमें आज भी उनके पिता के समकलीन अनुभवी नेता देखे जा सकते हैं, जिनकी सलाह तेजस्वी के लिए बहुत मायने रखती है। उधर, अखिलेश का जो इनर सर्किल है, उसमें सिर्फ उनके दोस्त रह गए हैं। दोस्त भी ऐसे, जिनका कोई जनाधार नहीं है। विधानसभा चुनाव में देखा गया कि उनके ज्यादातर दोस्त अपने बूथों पर ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जिता पाए। समाजवादी पार्टी की सरकार होने पर स्थानीय निकाय कोटे से उनके सभी दोस्त विधानपरिषद के सदस्य हो गए थे, लेकिन इस बार जब सरकार नहीं थी तो उसमें एक भी चुनाव नहीं जीत पाया और ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। पुराने नेताओं में सिर्फ एक राजेंद्र चौधरी ही अब अखिलेश के साथ देखे जाते हैं, लेकिन वह सलाह देने के लिए नहीं बल्कि अखिलेश की पसंद पर मुहर लगाने के लिए जाने जाते हैं।

उधर तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का पहला चुनाव 2020 में लड़ा गया। तब आरजेडी भले ही सत्ता में नहीं आ पाया, लेकिन नतीजों ने तेजस्वी के नेतृत्व का लोहा मनवा दिया।

तेजस्वी की क्यों हो रही चर्चा

नदीम।।

अखिलेश यादव को उम्र और राजनीतिक तजुर्बे, दोनों में ही तेजस्वी यादव के मुकाबले बढ़त हासिल है। अखिलेश 49 साल के होने को हैं, जबकि तेजस्वी अभी 32 के ही हुए हैं। अखिलेश साल 2000 से किसी न किसी सदन के सदस्य बनते रहे हैं, जबकि तेजस्वी का विधायक के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। अखिलेश लगातार पांच साल देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जबकि तेजस्वी के पास महज 20 महीने ही डेप्युटी सीएम रहने का अनुभव है। लेकिन नेतृत्व की कसौटी पर अगर इन दोनों युवा नेताओं को कसा जाए तो अखिलेश पर तेजस्वी बीस साबित होते दिखते हैं। अखिलेश के 2012 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ पांच सीटें जीत पाई। यह कहा जा सकता है कि 2014 में तो पार्टी की कमान उनके पिता मुलायम सिंह यादव के पास थी, लेकिन 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनावों में सब कुछ अखिलेश के हाथ में था और इन तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

2022 विधानसभा चुनाव में कांटे का मुकाबला होने की बात कही जा रही थी, लेकिन नतीजा आने पर पता चला कि समाजवादी पार्टी बहुत

पीछे रह गई। उसके हिस्से में महज 111 सीटें ही आईं, सहयोगियों के साथ भी वह केवल 125 सीट ही जीत पाई। उसके मुकाबले में बीजेपी थी, जिसने अकेले 255 सीटें जीतीं। उधर तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का पहला चुनाव 2020 में लड़ा गया। तब आरजेडी भले ही सत्ता में नहीं आ पाया, लेकिन नतीजों ने तेजस्वी के नेतृत्व का लोहा मनवा दिया। आरजेडी सदन में सबसे बड़ा दल बना और एनडीए के मुकाबले महागठबंधन सरकार बनाने में महज 15 सीट पीछे रह गया। इसी महीने हुए स्थानीय निकाय कोटे से यूपी विधान परिषद की 33 सीटों के चुनाव में अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई जबकि बिहार में 24 सीटों पर हुए चुनाव में विपक्ष में रहते हुए भी आरजेडी ने छह सीटों पर जीत दर्ज की।

पिछले हफ्ते अलग–अलग राज्यों की एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। उनमें से एक विधानसभा सीट बिहार की भी थी। यह सीट ऐसी थी, जो एनडीए के हिस्से की थी। इस पर दावेदारी को लेकर जिस तरह से बीजेपी और एनडीए के घटक दल वीआईपी में तकरार हुई और बीजेपी ने उस पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, उसके मद्देनजर यह उपचुनाव बीजेपी के साथ नीतीश सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त जब आरजेडी पर मुसलमानों और यादवों की पार्टी होने की तोहमत लग रही थी तो तेजस्वी ने कहा था कि वह आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते हैं। 2022 विधानपरिषद से लेकर विध ाानसभा उपचुनाव के नतीजे यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि तेजस्वी पार्टी को मुस्लिम–यादव के दायरे से बाहर निकाल कर उसे भूमिहारों तक ले जाने की रणनीति में कामयाब हुए हैं। उपचुनाव से पहले विधानपरिषद चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन में तेजस्वी ने जिस तरह की विविधता दिखाई, उसी से लगने लगा था कि वह अब पार्टी को सवर्ण वर्ग की भी स्वीकार्यता दिलाना चाहते हैं। विधानपरिषद चुनाव में तो उन्हें इसका फायदा मिला ही, विध ाानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने एनडीए को हराकर अपनी धमक दिखाई। उनका हश्र अखिलेश जैसा नहीं हुआ।

सूडोकू नवताल- 5347

***** कठिनतम

				1			6	
					5			
2		3	9			8		
6							5	
			8		3			
	1							4
		7			1	3		9
			2					
	5			6				

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू नवताल -5346 का हल

7	6	8	2	1	9	3	4	5
2	1	5	6	3	4	8	7	9
3	4	9	5	7	8	6	1	2
5	7	4	8	6	1	9	2	3
9	2	1	3	4	5	7	8	6
8	3	6	7	9	2	1	5	4
1	5	3	4	8	5	2	9	7
4	9	7	1	2	3	5	6	8
6	8	2	9	5	7	4	3	1

अपना ब्लॉग

कुछ सवाल 'पीड़ितों' से

मोहन। सरकारी कार्रवाई इस पूरे मामले का एक पहलू हैं। अगर इस मामले में हम 'पीड़ितों' से कुछ सवाल नहीं करेंगे तो शायद चर्चा अपने जायज अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी 'पीड़ित' जनता से मेरा कहना है कि जब आपका असली सरोकार इंसाफ न होकर अपने दुश्मन से बदला लेना हो, तो फिर आप शिकायत करना बंद कर दीजिए। मसलन शिवसेना से विवाद के बाद जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया, तो 'सामना' में बड़ी बेशर्मी से छापा गया३. गिरा दिया! और विडंबना देखिए जो लोग आज बुलडोजर न्याय से सबसे ज्यादा आहत हैं, उसे गलत बता रहे हैं। कंगना के दफ्तर गिराए जाने पर सबसे ज्यादा चटकारे इन्हीं लोगों ने लिए थे। जिन्होने चटकारे नहीं भी लिए वो जानबूझकर खामोश रहे क्योंकि वो अंदर ही अंदर मानते थे कि 'कंगना जैसी' के साथ ऐसा ही होना चाहिए था।